

प्रेषक,

कुँवर सिंह  
अपर सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
समस्त जनपद (हरिद्वार को छोड़कर)  
उत्तरांचल।

पेयजल अनुभाग

देहरादून: दिनांक 2 फरवरी, 2005

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत  
ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान कार्यालय, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून के पत्रांक कैम्प/धनावंटन प्रस्ताव दिनांक 22-01-2005 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या 926/उन्तीस/04/2(48पे0)/2004, दिनांक 27 अप्रैल, 2004 एवं संख्या 2580/उन्तीस/04/2(48 पे0)/2004, दिनांक 17 दिसम्बर, 2004 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जनपदवार निम्नलिखित विवरणानुसार कुल रू0 18,69, 02,000 (रू0 अठ्ठारह करोड़ उन्हत्तर लाख दो हजार मात्र) की धनराशि को व्यय हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-  
धनराशि (लाख रू0 में)

क्र० सं०	जनपद	परिव्यय	पूर्व अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	उत्तरकाशी	326.00	90.00	235.00
2	बमोली	172.20	72.00	99.00
3	रूद्रप्रयाग	231.00	90.00	140.00
4	टिहरी	542.80	355.00	186.80
5	देहरादून	218.50	108.00	109.70
6	पौड़ी	800.00	392.00	405.50
7	पिथौरागढ़	308.00	195.00	112.00
8	चम्पावत	254.34	90.00	163.18
9	अल्मोडा	274.62	195.33	78.47
10	बागेश्वर	228.67	90.00	137.77
11	नैनीताल	320.00	180.00	139.00
12	उधमसिंह नगर	99.80	36.00	63.00
	योग	3776.23	1893.33	1869.02

कमशा.2.

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उत्तरांचल पेयजल निगम के संबंधित जनपद के अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त तथा संबंधित जनपद के जिलाधिकारी के प्रतिहस्ताक्षरित बिल संबंधित जनपद के कोषागार में प्रस्तुत करके वास्तविक आवश्यकतानुसार पूर्व स्वीकृत धनराशि के 80 प्रतिशत उपयोग के उपरान्त ही किया जायेगा।

3- यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पूर्व स्वीकृत एवं उक्त स्वीकृत धनराशि का 31/03/2005 तक पूर्ण उपयोग हो जाय ताकि लाभार्थी तक त्वरित गति से लाभ पहुँचे। यदि समय पर उक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता है तो इसका और कार्य की गुणवत्ता का पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का ही होगा।

4- स्वीकृत धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों पर उ० प्र० शासन के वित्त लेखा अनुभाग -2 के शासनादेश सं०- ए-2-87(1)/दस-97-17(4)/75 दिनांक 27-2-97 के अनुसार सैन्टेज व्यय किया जायेगा तथा कार्यों की कुल लागत के सापेक्ष पूर्व में व्यय की गई धनराशि में सैन्टेज चार्ज के रूप में व्यय की गई धनराशि को समायोजित करते हुए कुल सैन्टेज चार्ज 12.50 प्रतिशत से अधिक अनुमन्य नहीं होगी। इस कृपया कड़ाई से सुनिश्चित कर आगणन में सैन्टेज की व्यवस्था उक्तानुसार ही की जाय।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रथमतः चालू योजनाओं पर किया जायेगा तथा चालू योजनायें शेष न होने पर ही नये कार्यों पर योजनावार विवरण उपलब्ध कराने पर शासन की अनुमति के उपरान्त ही धनराशि व्यय की जायेगी।

6- उक्त स्वीकृत धनराशि से जिला योजना में अनुमोदित ग्रामीण पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन उत्तरांचल पेयजल निगम द्वारा किया जायेगा। जनपदवार स्वीकृत धनराशि के योजनावार आवंटन की सूचना 2 सप्ताह के अन्दर शासन को अवश्य उपलब्ध करा दी जाय, जिसमें लाभान्वित होने वाली एन० सी० तथा पी० सी० बस्तियों का विवरण अवश्य स्पष्ट रूप से अंकित किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि ऐसी योजनाओं पर कदापि व्यय न की जाय, जिसके संबंध में तकनीकी स्वीकृति नहीं है अथवा जो विवादग्रस्त है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्वीकृत धनराशि जिला नियोजन तथा अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर एवं एन० सी० तथा पी० सी० बस्तियों के निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु व्यय की जायेगी।

8- व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाईनेन्शियल हैंडबुक नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अंतर्गत शासकीय अथवा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हों, उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय। निर्माण कार्यों पर व्यय करने से पूर्व आगणनों/पुनरीक्षित आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की टैक्निकल स्वीकृत अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

W

*[Handwritten signature]*




9- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता अथवा इस स्तर का अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। किसी भी दशा में एक योजना की धनराशि दूसरी योजना में कदापि व्यय न की जाय।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर लिया जायेगा तथा पूर्व स्वीकृत समस्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र यथासमय शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा। पूर्व स्वीकृत धनराशि के पूर्ण उपयोग के उपरान्त यथाआवश्यकता ही इस धनराशि का आहरण किया जायेगा। जिन जनपदों में पूर्व स्वीकृत धनराशि का उपयोग हो चुका हो, वे स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर सकते हैं।

11- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2004-05 के अनुदान संख्या -13 के लेखाशीर्षक - 2215-जलापूर्ति तथा सफाई 01-जलापूर्ति-आयोजनागत-102-ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम-91-जिला योजना-01-ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना-20-सहायक अनुदान/अंशदान राज सहायता के नामें डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय सं० 168/वि० अनु०-3/2005 दिनांक 01 फरवरी, 2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

  
(कुँवर सिंह)  
अपर सचिव

संख्या 2767 (1)/उन्तीस/04/2 ( 48 पे०)/2004, तददिनांक

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।

2- समस्त कौषाधिकारी, उत्तरांचल (जनपद हरिद्वार को छोड़कर)

3- मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमायूँ।

4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पेयजल निगम, देहरादून।

5- मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तरांचल जल संस्थान, देहरादून।

6- मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल/कुमायूँ) उत्तरांचल पेयजल निगम।

7- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।

8- वित्त अनुभाग-3/नियोजन प्रकोष्ठ/बजट सैल, उत्तरांचल शासन।

9- संयुक्त विकास आयुक्त गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।

10- आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तरांचल।


11-संबंधित अधिशासी अभियन्ता/नोडल अधिकारी, उत्तरांचल पेयजल निगम, संबंधित जनपद।

12- निदेशक, सूचना एवं लोक सर्मर्पक निदेशालय, देहरादून

13- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी,

14- निदेशक, एन०आई०सी० सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से

  
(कुँवर सिंह)

अपर सचिव